The question was put and the motion was adopted.

SHRI K. JANA KRISHNAMURTHY: Sir, I withdraw the Bill.

SHORT DURATION DISCUSSION

On Drought Situation in many parts of the Country

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद सभापति महोदय, इस समय लगभग सम्पूर्ण देश एक भयानक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। उसमें केवल किसान को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि देश में खेती पर मुनहासिर करने वाले करीब 100 में 70-75 लोग हैं। वे लोग केवल अनाज ही नहीं पैदा करते कारखानों में या दुकानों पर बैठे हुए लोग या दफ्तरों में काम करके तनख्वाह पाने वाले लोग अगर यह समझते हैं कि किसानों पर आफत आई है तो वे ऐसा कभी-कभी बोलते हैं। मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी दुकान पर जो सामान रखा है उसका असली खरीदार किसान है। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं रहेगा, खरीदारी की ताकत नहीं रहेगी तो तुम्हारी दुकान फीकी हो जाएगी। मैं तनख्वाह पाने वाले लोगों से कहना चाहता हूं जो चिंता कम करते हैं इस हालत पर, केवल गर्मी के माहौल से पसीना पौंछते हुए गर्मी की चर्चा करते हैं कि किसान गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है। तुम जो पहली तारीख को तनख्वाह लेते हो उस तनख्वाह से और नोटों की गड्डी से रोटी नहीं पक सकती और चावल नहीं पक सकता है। इसलिए मैंने जान बूझकर कहा कि सम्पूर्ण देश इस समय आफत में है और पता नहीं इसका अहसास सरकार कर पा रही है या नहीं। इसके विशेषज्ञों को सुनते हैं, कभी-कभी बोलते हैं। मंत्री जी भी कहते हैं कि दस सैकड़ा नुकसान हो गया खरीफ की फसल का। कई विशेषज्ञों ने बड़ा दबकर कहा कि 15 सैकड़ा नुकसान हुआ है खरीफ की फसल का। आज की तारीख में 25 सैकड़ा, 30 सैकड़ा खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है और अगर 15 दस दिन और पानी नहीं बरसा तो यह नुकसान 50 सैकड़ा तक जा सकता है। हमने दो-तीन दिन पहले सरकार का बयान पढ़ा कि यह सही है कि मोटा अनाज बाजरा या सोया अब नहीं पैदा हो सकता है और हम किसान को सलाह दे रहे हैं कि वह दूसरी फसल की बुआई करने के लिए सोचे। हम हंसने लगे कि आप दिल्ली से सलाह दे देंगे और किसान अपनी फसल बदलने लगेगा। इतना पढ़ा-लिखा विद्वान तो वह होता नहीं। यह सलाह देने की क्या जरूरत थी। अगर एक आफत आ गई है, इस आफत के बारे में मैंने सरकारी विभाग के कई लोगों से पूछा कि ऐसा सूखा और अकाल कभी पड़ा है या नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि 1987 जैसा सूखा अभी नहीं पड़ा है। हम दुखी हैं और सबसे ज्यादा दुखी खेत में काम करने वाला मजदूर है, जिसको खेतिहर मजदूर कहते हैं। इस समय वह धान की रुपाई पौधा उखाड़कर के किया करता था, वह मजदूरी करता था, वह बिहार से आता था, वह उत्तर प्रदेश से आता था, वह मेरठ से, हरियाणा से होते हुए पंजाब तक जाता था, वह तो भुखमरी की हालत में पहुंच गया है। किसान लोग जिनके पास थोड़ा-बहुत पैसा होगा, वे खरीद कर के खा-पी सकते हैं, वे कहीं न कहीं से, बाहर से अनाज मंगायेंगे, लेकिन वह बेचारा तो खरीद कर भी नहीं खा सकता है, क्योंकि उसकी जेब में तो पैसा ही नहीं होगा। वह कहां से खरीदेगा, यह एक बहुत ही भयानक स्थिति है। इस स्थिति को जो लोग सत्ता में हैं या जो अफसरशाही है, वह अजीब ढंग से काम कर रही है। हमने कई बार इलाहाबाद में और दूसरी जगहों पर सूखे के सवाल पर प्रदर्शन किया है। वहां के कलेक्टर ने कभी इस पर नोटिस नहीं लिया। वे यह सोचते हैं कि पांच दिनों के बाद पानी तो बरस ही जायेगा, उसके बाद यह सवाल इरेलीवेंट हो जायेगा, असंगत हो जायेगा और सरकार भी सोचती

है कि कभी न कभी तो पानी बरसेगा ही। लेकिन अब की बार पानी बरसने का नाम आसमान नहीं ले रहा है। हमारा मौसम विभाग पहले बोला था कि 29 जून तक पानी बरस जायेगा। हिन्दुस्तान में तसल्ली हुई थी कि शायद बरस जायेगा। दिल्ली में पानी बरस जायेगा, उसने यह बात कही थी, क्योंकि केरल के तट पर और बंगाल की खाड़ी में थोड़ा बहुत मानसून तेज हुआ था। यहां दिल्ली में बैठे हुए हमारे मौसम विभाग के अफसर एक बार तो चटक गए कि 20 जून तक दिल्ली में पानी आ रहा है। दिल्ली के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि एक मामूली सा झटका पानी का आ गया, लेकिन वह मानसून नहीं था। लोगों ने कहा- पहली राहत मिल गई। उसके बाद पानी नहीं आया। फिर उसने कहा कि 10 जुलाई तक जरूर पानी बरसेगा, लेकिन फिर भी पानी नहीं बरस रहा है। लोग कहते हैं कि वक्त आने पर पानी बरस जायेगा। मैं चाहूंगा कि मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी काबिलियत के बारे में कोई नये सिरे से इम्तहान लिया जाय। वे इतने निकम्मे हैं कि वे मौसम को ठीक से समझ नहीं सकते, तो मैं उनसे कहूंगा कि घाघ की छोटी-छोटी किताबें पढ़ लिया करें। हिन्दुस्तान में घाघ हुआ था जिसकी किवदंतियां हैं। वह मौसम के बारे में बोल दिया करता था और जो बोल दिया करता था, वह अचूक होता था। वे उसको थोड़ा-बहुत पढ़ लिया करें तो आपको मालूम हो जायेगा कि मौसम का कैसे अध्ययन किया जाता है। पूर्वानुमान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।

सभापति महोदय, मैं कल टेलिविजन पर मौसम विभाग के एक अधिकारी का बयान सुन रहा था। उसने कहा कि सारे हिन्दुस्तान में ऐसी हालत नहीं है, कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है। यह सुनकर हमको हंसी आ रही थी कि यह बोल कैसे रहा है। हिन्दुस्तान के मामूली से टुकड़े में थोड़ा अनाज पैदा हो जाए तो सौ करोड़ से ऊपर की आबादी को खाना खिलाने के लिए वह काफी नहीं होगा। वह इस हकीकत को नहीं जानता है। वह अब भी नहीं बोलता है कि हमारा मौसम विभाग गलत नहीं बोलता है। लेकिन यह सच है कि मानसून वापस लौट गया है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए और सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने इसके लिए क्या कंटेंजेंसी प्लान बनाया है? मैं जानता हूं कि केन्द्र सरकार कह देगी कि राहत का मुख्य काम राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की हैं। वे सरकार बयान देने लगेंगी कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, भेद-भावपूर्ण नीति बन रही है। गांव का किसान, खेत में काम करने वाला मजदूर तो एक महीने बाद की तकदीर के बारे में सोच रहा है। वह केवल आसमान की तरफ देखता है, वह सरकार की तरफ नहीं देखता है, क्योंकि सरकार तो बोल देगी कि पानी नहीं बरसा तो वह क्या करे। अगर पानी ठीक से बरस जाए तो यही सरकार बोलेगी कि देख लीजिए अटल जी के राज में कितनी बढ़िया फसल हुई है और पानी ठीक से नहीं बरसा तो ये लोग आसमान की तरफ इशारा कर देंगे कि इन्द्र भगवान नाराज हो गए। जिम्मेवारी-जिम्मेवारी हुआ करती है। अगर फसल बढ़िया होती है तो उसकी जिम्मेवारी यह सरकार लेती है, उसका सेहरा यह सरकार अपने सिर पर लेती है, लेकिन अगर फसल खराब हो गई है तो इसकी जिम्मेवारी भी इस सरकार को लेनी चाहिए। राज्य सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ सकते । राज्य सरकारें आम तौर से दीवालिया हैं, वे अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं बांट पा रही हैं, चार-चार, छः-छः महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और वे केन्द्र सरकार से तनख्वाह बांटने तक के लिए पैसा मांग रही हैं कि आप पैसा दे दो तो हम तनख्वाहें बांट दें । अगर आपने उनके ऊपर छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी । राज्य सरकार को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी । उड़ीसा के लोगों की रिपोर्ट आ रही है कि अकाल की स्थिति आ जाएगी । लोगों ने अपने जानवर छोड़ दिये कि

जाओ, जहां चाहे चरो । पूरे उत्तर प्रदेश की हालत खराब हो गयी । महोदय, पुराने हिन्दुस्तान में भी अकाल पड़ा था । राजा जनक के जमाने में एक बार अकाल पड़ा था । वे राजा थे पर अकाल तोड़ने के लिए, पानी बरसाने के लिए खुद उन्होंने हल चलाना शुरू किया क्योंकि यह किदवंतियां थी, यह अंध विश्वास था कि अगर राजा हल चलाएगा तो पानी बरस जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लेकर गोरखपुर, देवरिया तक, पूरे उत्तर प्रदेश में इन इलाकों की औरतें रात को नंगा होकर हल चला रही हैं कि इंद्र देवता खुश हो जाओ, पानी बरसाओ । यह अखबारों में छप रहा है । परसों अलीगढ़ की खबर छपी थी कि औरत नंगा होकर हल चला रही है ताकि भगवान खुश हो जाएं । हम देवरिया गए, गोरखपुर गए, देवरिया में सूखे के समय में हरपौड़ी मनाया जाता है । महिलाएं नंगा होकर हल चलाती हैं । हमारे इलाहाबाद में बताया गया कि एक नाई की औरत ने नंगा होकर हल चलाया ताकि भगवान खुश हो जाएं । जब राजा हल नहीं चलाया करता, अंध विश्वासों के तहत ही, तो हिन्दुस्तान की महिला निर्वस्त्र होकर हल चलाया करती है कि भगवान खुश हो जाएं । कितने दिनों तक क़मजोर वर्ग को अपमानित करके हम इस दैवी आपदा का मुकाबला करेंगे ? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं । यह सच है कि हमारे यहां किस्से हैं कि एक बार पानी नहीं बरस रहा था तो एक शूद्र का बेटा अनशन पर बैठ गया, तपस्या पर बैठ गया । राजा को बहुत बुरा लगा - बाद में हमने उसको भगवान भी मान लिया - उसने जाकर उस हरिजन के बेटे को तीर मार दिया, वह मर गया । हम गरीब लोग तपस्या करें तो हमें तीर मारा जाए । दलित और औरत अंधविश्वास के नाम पर कितने दिनों तक दैवी आपदाओं का शिकार बनकर रहेगी ? क्यों नहीं राजा लोग, जो गद्दी पर बैठे रहते हैं, एक बार अटल जी राजा जनक बन जाएं, हल चलाने लगें, अगर इसी से पानी बरसता है तो । महोदय, मैं कह रहा था कि दैवी आपदाएं लंबे अरसे से आती रहती हैं । अटल जी हों, आडवाणी जी हों, अजीत सिंह जी हों, क्यों नहीं यह लोग ऐसा करते ? क्यों यह औरतों के जिम्मे रहा है ? और यह किस्सा क्या सच नहीं है कि पानी के अभाव में महिलाएं पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में नंगा होकर हल चला रही हैं । हमने एक दिन अपनी मीटिंग में कह दिया कि हमारे देवरिया में ऐसा हो गया । उसके दूसरी दिन अलीगढ़ का छप गया तो राम गोपाल जी बैठे थे, इन्होंने कहा कि हमारे इटावा में भी ऐसा होता है । हमारे एक साथी ने कह दिया कि यह पुराना अंधविश्वास है। यह अंध विश्वास इसलिए है क्योंकि हमें आपसे उम्मीद नहीं है । जनता को जो खेती करती है, उसे सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और अंधविश्वास के तहत वह भगवान को, आसमान को खुश करने के लिए पता नहीं कितनी खुराफात का शिकार होती चली जा रही है और याद रखिए, जिस देश की मातृ शक्ति अभाव के कारण खेत में नंगा होकर हल चलाती है, वह देश कभी मजबूत नहीं हो सकता । हम कुर्सी पर बैठकर, पार्लियामेंट में आकर सत्ता के नशे में या और किसी नशे में चूर हो रहे हैं और देश की जनता, उसकी मातृ शक्ति नंगा होकर हल चलाए, यह एक बेहिसाब किस्म के अपमान की स्थिति है । मैं सूखा और भूख को भयानक मानता हूं कि उसके चलते हिन्दुस्तान की महिला किसी गरिमामय रास्ते से हटकर इतने गलीज रास्ते पर किसी मजबूरी में चली जाए । मैं चाहूंगा कि अजीत सिंह जी केवल सूखे का मुकाबला करने के लिए कंटिनजेंसी प्लान नहीं, बल्कि उन अंधविश्वासों से लड़ने के लिए भी कोई न कोई योजना जरूर बनाइएगा क्योंकि समाज का कोई भी कमजोर वर्ग अंध विश्वासों के तहत आकर किसी आफत का मुकाबला करता है और अपमानित स्थिति में जाकर करता है तो वह बहुत खतरनाक है ।

उसका मुकाबला करने की ज़रूरत पड़े तो उनसे कह देना कि तुम्हारे नंगा होकर हल चलाने से अगर इंद्र भगवान खुश होते हों तो तुम अपने गांव में ऐसा मत करना, हम दिल्ली में

1713 GIPMR/03—15

ही यह काम खुद कर देंगे और इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे । इन अंधविश्वासों से लड़ने के लिए थोड़ा अपनी तरफ से हिम्मत दिखानी पड़ेगी । मैं जानता हूं कि खेती को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया । इसको नंबर दो का विषय माना गया । उद्योग, व्यापार और वे धंधे जो रुपए से रुपया कमाते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने के बाद उन्हीं धंधों को महत्व दिया गया । थोड़ा सा चौधरी चरण सिंह के ज़माने में, थोड़ा सा मैं जान-बूझ कर कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको महत्व देने की कोशिश की गई थी। इस समय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत में उनके बेटे कृषि मंत्री हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वे थोड़ा सा इस बात पर सोचेंगे । थोड़ा सा उन्होंने एक बार कह दिया था जब वे वित्त मंत्री थे कि ये टूथपेस्ट जो मल्टी नेशनल कंपनियों के हैं, इनका इस्तेमाल मत करो, दातुन का इस्तेमाल करो । मुझे याद है कि जो भद्र पुरुष हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने इसका कितना बुरा माना था लेकिन दृष्टि तो अलग थी । मैं चाहूंगा कि उसी दृष्टि का इस्तेमाल फिर किया जाए ।

दूसरी बात यह है कि आफत आ रही है और इस आफत का मुकाबला करने के लिए एक अजीब हालत हो रही है । हालत यह हो रही है कि दो महीने बाद जब गांव के स्कूल खुलेंगे तो बच्चों के मां-बाप फीस नहीं दे पाएंगे और उन बच्चों का नाम स्कूल से कट जाएगा । हालत यह हो रही है कि गांव का किसान चार महीने बाद सरकार का जो देय है, वह अदा नहीं कर पाएगा तो उसके खेत-खलिहान और उसकी बीवी के जेवर बिक जाएंगे । हालत यह हो रही है कि जो खेतों में मज़दूरी करते हैं, एक महीने बाद वे दाने-दाने के लिए तरसने लगेंगे और भूखों मर जाएंगे । एक अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है । अगर दस दिनों के अंदर पानी नहीं बरसा तो यह हालत हो जाएगी । दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है, एक तरफ तो आसमान में पानी नहीं है और दूसरी तरफ हमें ज़मीन पर भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है । ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल): आंखों में पानी नहीं है ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): क्या सरकार की आंखों में पानी नहीं है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, दिल्ली की हालत यह हो गई है कि कई मोहल्लों में दो-तीन दिनों से पीने का पानी नहीं है । ज़मीन के नीचे का पानी निकालने के लिए भी तो बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा । गांवों में बिजली आठ-आठ, दस-दस दिनों तक गायब रहती है । अभी मैं अपने गांव गया था, तीन दिन वहां रहा और उन तीन दिनों में एक घंटे के लिए भी बिजली नहीं आई । मैंने कलेक्टर से पूछा कि क्या कर रहे हो, बिजली तो दिलवाओ, पंखा तो चल जाए तो उसने कहा कि क्या करें, बिजली है ही नहीं । यह हालत है गांवों की । छोटे कस्बों की भी यही हालत है । वहां बिजली नहीं मिलती है । दिल्ली शहर में बिजली गायब है । खैर यह तो राजधानी है, यहां हल्ला-गुल्ला करके लोग बिजली ले ही लिया करते हैं लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में बिजली नहीं मिलती है । बिना बिजली के ज़मीन के नीचे का पानी नहीं निकल सकता है । ज़मीन के नीचे के पानी की सतह भी नीची होती चली जा रही है, उसको निकालने में भी दिक्कत है । हमने गया के बारे में पढ़ा कि वहां के किसान थोड़ा स्वयंसेवकी करके, वॉल्यंटरी करके कुछ तालाब भर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में तालाबों की यह हालत हो गई है कि एक भी तालाब नहीं रह गया है । जो भी दबंग आदमी हुआ, उसने तालाब पर कब्ज़ा करके अपना मकान बना लिया । पट्टे हो गए सरकार की तरफ से । यह हालत हो गई है तालाबों की,

दुर्दशा की हालत है । कहीं भी कोई भी तालाब दिखाई नहीं देता है गांवों में । वह रखा तो इसलिए जाता था कि कभी आफत आएगी तो तालाब को भरकर पानी रखा जाएगा ताकि खेतों की सिंचाई हो सके, वह नहीं है। हमने गया के किसानों के बारे में पढ़ा कि वे तालाब भरने का कोई रास्ता निकाल रहे हैं, लड़के खुदाई कर रहे हैं । उस खुदाई का कोई मतलब नहीं होता है अगर वहां पानी नहीं है भरने के लिए । एक भयानक किस्म की स्थिति है । ज़मीन के नीचे पानी नहीं है, आसमान में पानी नहीं है । पहले कहा जाता था कि अगर पानी है तो जो खेत में पानी गिरता है, वह खेत का है, जो गांव में पानी गिरता है वह गांव का है और जो आसमान से पानी गिरता है, वह पाताल का है । पाताल का पानी गायब हो रहा है । आसमान का पानी बरस ही नहीं रहा है । खेत का पानी सूख गया है और गांव का पानी जो तालाब वगैरह का था, वह सब खत्म हो गया है ।

हमने गया के लोगों के बारे में आज ही अखबार में पढ़ा कि वे वालेंटरी तालाब खोद रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं । तो हमको संतोष हुआ, लेकिन वे करेंगे क्या? ऐसी हालत में हमको सोचना पड़ेगा। मैं कोई कटु होकर नहीं बोल रहा हूं, कोई विरोधी की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं। अपने दिल का दर्द बता रहा हूं कि भयानक स्थिति आने वाली है, बहुत भयानक। शायद वह स्थिति आ जाए कि शायद लोग भूख से तड़प-तड़पकर सड़क पर मर जाएं। लोगों को खाने के लिए ही नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। हमारे देश में खाने की चीज पैदा नहीं होगी। मैं कारखानेदारों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा कपड़ा अगर नहीं बनेगा तो हम बिना कपड़े के जी सकते हैं। तुम्हारी सीमेंट नहीं बनेगी तो हम बिना सीमेंट के जी सकते हैं। लेकिन बिना रोटी और चावल के हम जी नहीं सकते। सब्जियां सूख गई, उनके भाव चढ़ गए। हो सकता है कि 15-20 दिनों के बाद हम लोग बिना सब्जी के खाना खाएं। हो सकता है कि कोई फसल न हो सके, बाजार बिगड़ जाएं तो उस समय हम बिना रोटी के दो-रात तीन रात गुजार दें। देश की जब ऐसी तस्वीर बन जाया करती है कि आम जनता अपनी दैनिक जिंदगी की जरूरत से जूझने लगती है, उसके मन की सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं और देश की जब यह हालत हो जाती है कि सत्ता में बैठे हुए लोग धुत्त होकर देश के लोगों की परवाह न किया करें। गौतम जी की निगाह में उनकी तब आंख का पानी मर जाता है। सरहद पर दुश्मन सक्रिय है। वही मौका हुआ करता है दुश्मन की हरकत का। वह जानता है कि देश को कमजोर किया गया है। वह जानता है कि जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है। वह जानता है कि सत्ता नशे में है। कुर्सी का नशा भी बड़ा हुआ करता है और पता नहीं कितने किस्म के नशे अखबारों में छप रहे हैं। ऐसी हालत में जब मुल्क कमजोर होगा तो महोदय, दुश्मन हम पर कब्जा करने की कोशिश में है। कई देशों के इतिहास और हमारे देश के इतिहास भी कई पन्नें में भरे हैं कि हमारे राजा और महाराजा अय्याशी में मस्त थे, जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी तब दुश्मन ने कब्जा कर लिया। बड़ी भयानक स्थिति है। यह थाली की रोटी का सवाल नहीं है, पानी का सवाल नहीं है, औरत की इज्जत का सवाल नहीं बल्कि सोचिए की मुल्क की अस्मिता और उसकी आजादी का सवाल है, जो आकर फंस गया है। इसलिए मैं अजित सिंह जी से आपकी मार्फत सवाल करूंगा कि हिम्मत है तो इस स्थिति का मुकाबला आपकी कैबिनेट नहीं कर पाएगी, मैं जानता हूं। इसमें अफसर हैं, वे जो सलाह देंगे, वह बेमतलब की होगी। जो बैठते हैं, वही बोला करते हैं। मैं उनकी पढ़ाई लिखाई जानता हूं, अच्छा सर। अगर ये अफसर गांव के ही किसान के बेटे हैं, इनको खेती के बारे में जानकारी होती है तो ये अफसरी की नौकरी करने आते? ये तो नौकरी इसीलिए करते हैं कि खेती से भागने की इच्छा थी। बड़ी मेहनत का काम है, गंदा काम है, धूल लगती है और कपड़े

गंदे होते हैं। ये इसीलिए आकर आफिसर या दूसरे धंधे में जाते हैं। ये हमारे ही बेटे हैं लेकिन इनकी दिलचस्पी नहीं है। अजित सिंह जी भी नहीं जानते होंगे, उनकी दिलचस्पी भी हम जानते हैं। चौधरी साहब बोला करते थे कि मैं तो किसान का बेटा हूं, थोड़ी बहुत खेती जानता हूं, बैल की रस्सी पकड़ सकता हूं लेकिन मेरा बेटा तो किसान का बेटा नहीं है, वह बैल की रस्सी नहीं पकड़ सकता। उनके हाथ में हिन्दुस्तान की कृषि व्यवस्था दी गई है। चौधरी साहब ने यहां हम लोगों से कहा था कि किसान कैसे हो सकता है? मैं तो हूं क्योंकि मेरा बाप किसान था। मैंने दरवाजे पर बैल की रस्सी पकड़ी है, उसका नाता है। फिर भी खून तो है, संस्कार तो हैं। मैं उसकी बुनियाद पर इनसे अपील करूंगा कि जरा बहुत बढ़िया हिम्मत दिखाइये। यह सही है कि हम कई युद्धों की चर्चा किया करते हैं। कलाम साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक हथियार ऐसा दे दिया कि दुनिया के उस हथियार की लाइन में हम चले गए। कई बार, कई तरह की चर्चाएं करते रहते हैं, दुश्मन देश से। लेकिन हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय भुखमरी, गरीबी होने जा रही है। इस दुश्मन से लड़ने के लिए कौन सी नीति यह सरकार बनाएगी? इसके लिए आफत के रूप में कई रास्ते आएंगे, कभी कुदरत आएगी। हिन्दुस्तान की भौगोलिक स्थिति का नक्शा इतना अजीब है कि किसी एक देश में इतने किस्म का भूगोल नहीं होता।

हिमालय से लेकर अरब सागर के किनारे और इधर बंगाल की खाड़ी के किनारे कितने किस्म का भूगोल है । यह कभी-कभी हमारे लिए वरदान होता है और कभी-कभी अभिशाप होता है । आज अभिशाप बनकर आया है इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री और सरकार इसे गंभीरता से लें । लोगों की फसल सूख गई है । सूखा या अकाल घोषित करने के क्या पैमाने हुआ करते हैं ? क्या आज वह स्थिति नहीं आ गई है ? आप इंतजार कर रहे हैं कि दस दिनों में पानी बरस जाए और सूखा घोषित न किया जाए । पूरे देश को सूखा घोषित किया जाना चाहिए। सूखा घोषित करने का मतलब यही होता है कि जितने सरकारी देय हैं वे किसान से नहीं लिए जाएं । जो चालाक सरकारें होती हैं वे उन्हें मुल्तवी करती हैं लेकिन मै मांग करूंगा वे सारे के सारे माफ किए जाएं । जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनके खाने का कोई इंतजाम नहीं है, उनके लिए राहत कार्य खोले जाने चाहिएं, तालाब खुदवाने चाहिएं तथा अन्य दूसरे कार्य जैसे काम के बदले अनाज की योजना चलाई जानी चाहिए । जब अभाव आता है तो छोटे-छोटे बच्चे और बूढ़े जो न काम कर सकते हैं, न काम के बदले अनाज ले सकते हैं वे कुपोषण का शिकार होकर मर जाया करते हैं । सरकार को दिल खोलकर इस पर फैसला करना चाहिए । खंड भोजनालय, ब्लॉक के तौर पर अपाहिज किस्म के लोगों के लिए, जिनके खाने का इंतजाम नहीं है, कम से कम उनके लिए तो एक जून, दो जून की रोटी का इंतजाम किया जाए । रजिस्टर बनाकर किया जाए । लाम भोजनालाय, सबके लिए, जो अपाहिज हैं उनके लिए और जो काम करने लायक हैं उनके लिए काम के बदले अनाज । जो किसान हैं उनके बेटों की फीस माफ होनी चाहिए, उनके सारे सरकारी देय माफ होने चाहिए । आज उत्तर प्रदेश का किसान ऐसी चपेट में फंसा है कि जब मैं उनसे बात करता हूं तो वह रोने लगता है । समझता है कि नेता है । इसने हमारे सुख-दुख में काम किया है । उसके साथ वाकई जज्बाती रिश्ते हैं लेकिन आज वह जिस चपेट में फंसा हुआ है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं । हमने इतना कहा कि तुम आसमान मत देखो, सड़क पर उतरना सीखो । सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह तुम्हारे खेत-खलिहान की हिफाजत करे, पानी बिजली का इंतजाम करे । उत्तर प्रदेश में बिजली बिल्कुल नहीं है, फेल हो गई है । वहां की सरकार बार-बार कहती है कि हम बिजली दिलाएंगे । अधिकारियों को

कसना चाहती है लेकिन लगता है कि उसकी मुट्ठी कमजोर है क्योंकि दो सोच के लोग वहां मिल गए हैं । मैं चाहूंगा कि इस पूरी भयानक स्थिति में राज्य सरकार को अपने पर न छोड़ा जाए । केंद्र सरकार को कंटीन्जेंसी प्लान बनाना चाहिए जहां सूखा पड़ा है । सूखे में कोई एक क्षेत्र नहीं है । कितने सूखाग्रस्त गांव चुन लिए गए हैं ? अगर बीस गांव सूखाग्रस्त मान लिए जाएं, उसकी बगल में पानी नहीं बरसे तो दूसरा गांव भी सूखाग्रस्त हो जाएगा । उत्तर प्रदेश के सारे के सारे गांव सूखाग्रस्त घोषित किए जाएं और उसके बाद सूखाग्रस्त क्षेत्र का पैमाना बताया जाए । अब तक जो पैमाना चलता रहा है वही चलेगा लेकिन आज उससे आगे बढ़कर खोजना होगा । लोकतंत्र के बहुत साल हो गए । लोग जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं । गांव का किसान बहुत पढ़ा-लिखा नहीं होता । वह अनजाने भगवान की तरफ देखा करता है । आज उत्तर प्रदेश का किसान चलते-फिरते भगवानों की तरफ भी देख रहा है कि वे ही हमें राहत देंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी और इस विषय पर बेमतलब की बहस नहीं करेगी कि पंद्रह सैकड़ा, तेरह सैकड़ा या पच्चीस सैकड़ा का नुकसान हो गया है । यह अफसरशाही आपको फंसा देगी । किसी के दर्द को समझने के लिए अफसरशाही के पैमाने का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि यह बहुत गलत किस्म का थर्मामीटर होता है । किसी के दर्द को समझने के लिए उसके दरवाजे तक जाना पड़ेगा तब आप समझ जाएंगे कि वह किस हालत में है। धान कि जो बेहन बोई गई थी उसमें पानी तो रखा गया था लेकिन धूप की रोशनी से वह ऊपर ही ऊपर सूख गई ।

यह एक भयानक स्थिति है। मैं नहीं जानता कि सरकार इन पूरी परिस्थितियों से वाकिफ है कि नहीं। अगर वाकिफ है तो उसे वक्त रहते उठ जाना पड़ेगा और एक-दो दिन के अंदर ही, यह नहीं कि कैबिनेट दस दिन के बाद तय करेगी। 15 दिनों तक तो पानी बरस ही जाएगा। अब हमको क्या करना है, यह आफत को टालने के लिए अफसरशाही तरीका हुआ करता है। उससे अलग हटकर सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, इस मानसून सत्र में हम सूखे की भयावह स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। यह विडम्बना है कि मानसून समय पर न आने के कारण मानसून सत्र की जो रौनक है वह फीकी पड़ गयी है। सरकार की रौनक तो फीकी पड़ी ही हुई है। मान्यवर, यह बड़ी अजीबोगरीब बात है कि देश के सत्ता सूत्र को संभालने वालों के लिए, चर्चा करने के लिए, बहस के लिए कई विषय होते हैं, वे विषय भी महतवपूर्ण हुआ करते हैं, मैं उससे इन्कार नहीं करता, लेकिन प्राथमिकता और वरीयता किन विषयों को दी जानी चाहिए, यह हम जैसे प्रतिनिधियों के लिए एक सोच का विषय है और निश्चित रूप से मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्राथमिकता और वरीयता वाले विषयों की जब बात आती है तो सूखे जैसे विषय को बहुत पीछे रखा जाता है। कृपापूर्वक आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज अवसर प्रदान किया है।

आज स्थिति यह है कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा इन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में है। मान्यवर, इस देश के 12-13 ऐसे राज्य हैं जो लगभग हर बार सूखे की चपेट में आते हैं। स्थिति यह बनी हुई है। माननीय मिश्र जी ने यह कहा कि हम आंकड़ों के जाल में न फंसे। लेकिन हम वास्तविकता को नकार नहीं सकते। स्थिति यह है कि 50 वर्ष के बाद भी जो 60 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले इन्सान, किसान हैं वे आज भी बारिश पर अवलम्बित हैं, आलम्बित हैं। वे इस बात की फिक्र करते हैं कि इन्द्र देवता प्रसन्न हो जाएं ताकि समय पर बारिश हो जाए

और उन कृषकों को सूखे जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। आज स्थिति यह है कि जब मैं कह रहा हूं कि इस देश का अधिकांश भाग सूखे की चपेट में है तो मुझे यह कहने की भी इजाजत दीजिए कि पांच करोड़ से ज्यादा लोग इस सूखे की वजह से खाद्यान्न और पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति बन गयी है, इसकी विकरालता की स्थिति यह हो गयी है। मानसून के मौसम में हालत यह है कि किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है और मानसून समय पर नहीं आ पा रहा है। उसकी स्थिति यह बन गयी है।

मैं जिस प्रदेश मध्य प्रदेश से आता हूं, उस मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, कर्णाटक, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं, और ऐसे अनेक राज्य हैं जो सूखे की चपेट में हैं। लेकिन समय पर हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। हर बार जब सदन में ऐसा अवसर आता है, हम चर्चा करते हैं। लेकिन इसका कुछ दीर्घकालिक उपाय हम नहीं खोज पाते हैं। हम कोई दीर्घकालिक नीति तय नहीं कर पाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि हर बार या तो सूखे की स्थिति पर चर्चा करते हैं या कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ की स्थिति पर चर्चा किया करते हैं।

मान्यवर, प्रतिवर्ष इस सूखे की वजह से अरबों-खरबों का नुक्सान हो रहा है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो समय पर नीति अपनायी जानी चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए वे कदम नहीं उठाए जाते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी का वक्तव्य मैंने पिछले सप्ताह सुना था। उन्होंने कहा कि अब अगर समय पर और बारिश नहीं आई तो हमको सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने पड़ेंगे। कई राज्यों में हमको घोषित करने पड़ेंगे। प्रश्न यह है कि हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं। ईश्वर करे यह न हो, लेकिन आगे अगर बारिश न हो तो हम क्या कदम उठाएंगे। किसानों को बताया जाए कि वे कौन सी फसल बोएं जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े।

मिसाल के तौर पर, क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंधित हूं इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं अगर बारिश समय पर नहीं आती है, सूखा पड़ता है और सोयाबीन की फसल यदि बोई जाती है तो उसकी पैदावार नहीं हो सकती है । मैं उस मध्य प्रदेश से आता हूं जहां हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा सोयाबीन की पैदावार होती थी लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि सूखे की स्थिति हो गई है इसलिए वहां किसानों ने सोयाबीन बोना बंद कर दिया है । वहां बाजरे की बुवाई हो रही है । अन्य चीज़ों की बुवाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को निर्देश दिए हैं । इस प्रकार के निर्देश समय पर दिए जाने जरूरी हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय में हमारा मौसम विभाग क्या कर रहा है । हम कहते हैं सूखा संहिता बननी चाहिए । ठीक है, सूखा संहिता बने, जो बताए कि सूखे से निपटने के लिए किसान क्या कदम उठाएं, लेकिन इस बारे में मौसम संहिता भी बननी चाहिए । यह जो अंतरिक्ष विभाग है यह क्या कर रहा है । मान्यवर, अंतरिक्ष विभाग का एक विंग ऐसा है कि जो यह बताता है कि देश के किन भागों में सूखा पड़ने का अंदेशा है । एक विभाग ऐसा है जो बता देता है कि देश के किन भागों में पानी की कमी होने वाली है । जब वह यह पहले से इंगित कर देता है तो उस इलाके में पहले से हम काम क्यों नहीं करते हैं? कई प्रकार की योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और कई प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं । उन योजनाओं को प्रारंभ से ही उन इलाकों में क्यों नहीं लागू किया जाता है, यह एक सोचने और विचारने की बात है । हमारे देश में हम यह कहते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने काफी तरक्की कर ली, लेकिन उसका हम अभी तक क्या

लाभ ले पा रहे हैं, यह देखने की बात है । हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। मोटे अनुमान से हालत यह है कि हमारे देश की 4 प्रतिशत भूमि नहरों से सींची जाती है। हमारे यहां नदियों की बाढ़ है, एक तरीके से अपरमपार नदियां हैं, लेकिन उनका जो अपरमपार पानी है उसका हम समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । कुछ जगह तो स्थिति यह है कि पानी बह जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है । कुछ जगह स्थिति यह है कि पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है तो वहां उपयोग करने की स्थिति क्या हो सकती है, इस बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं । मान्यवर, सब से महत्वपूर्ण समस्या है कि आखिर सूखे के मूल में क्या है । इस सब के पीछे कारण यह है कि हम जल संग्रहण की कोई नीति नहीं बना पाए हैं । कंज़र्वेशन ऑफ़ वॉटर की हम कोई नीति नहीं बना पा रहे हैं। जो एक्सप्लोयटेशन ऑफ़ वॉटर है उसको रोकने के लिए हमें कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं । जो रेन वॉटर हॉरवेस्टिंग है उसका समुचित उपयोग हो, उसके लिए हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं और स्थिति यह हो रही है कि जल संरक्षण नहीं हो पा रहा है । रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोपर नहीं हो पा रही है । ग्राउंड वॉटर का एक्सप्लोयटेशन हम रोक नहीं पा रहे हैं और अब बारिश की कमी हो रही है तो अवर्षा के कारण हमारे देश के कई प्रदेशों को सूखे की स्थिति से निपटना पड़ रहा है । जैसे मैंने कहा, मान्यवर, मैं उस प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश से जो सूखे की चपेट में है, वहां स्थिति यह है कि अवर्षा के कारण 50 प्रतिशत से अधिक खरीफ की फसल हो नहीं पा रही है, किसान उसे बो नहीं पा रहे हैं । वहां 34 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कम वर्षा हुई है । जो सामान्य वर्षा होती है वह 262 मि0मी0 होती है । लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में जो वर्षा हुई है वह 159 मि0मी0 ही हो पायी है । यह मैं केवल मध्य प्रदेश की स्थिति का जिक्र कर रहा हूं । स्थिति यह है कि जो सूखा ग्रस्त शहर हैं, उसके 36 शहर ऐसे हैं जहां अल्प वर्षा के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है । आपने टीवी में सुना होगा कि भोपाल में पुराने भोपाल को एक दिन पानी दिया जा रहा है और नए भोपाल को दूसरे दिन पानी दिया जा रहा है । यह नगरीय प्रशासन वाली स्थिति का मैं आपको वर्णन कर रहा हूं । इसलिए इस विषय में इस स्थिति का कोई स्थायी निदान निकालने की जरूरत है । आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम प्रति वर्ष इस पर चर्चा करें और चर्चा करने के बाद एक औपचारिकता हम पूर्ण कर लें और इससे हम अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मान लें । स्थिति यह है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि सूखे के प्रभाव से क्या-क्या असर होता है । इससे पर्यावरण पर असर होता है और जब पर्यावरण पर असर होता है तो स्थिति यह है कि फसल और वनोपज की पैदावार में काफी कमी आ जाती है । स्थिति यह है कि इससे जल स्तर में गिरावट आ जाती है ।

महोदय, जब हम इस के सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो पाते हैं कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाता है । इस में खास तौर से महिलाएं शिकार होती हैं और महिलाओं को रोजगार न मिलने की वजह से उन्हें कई प्रकार की असहनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है जिस का बहुत ही संवेदनशील चित्रण अभी आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने प्रस्तुत किया है । उन का लोग शोषण करते हैं और उन्हें शोषण सहने के लिए मजबूर होना पड़ता है । इस के सामाजिक प्रभाव से गरीबी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, पुनर्वास की समस्या बढ़ जाती है, जानवरों के लिए चारे की समस्या हो जाती है क्योंकि अवर्षा की स्थिति के कारण चारा नहीं हो पाता है, जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होता है, गांवों से शहरों में लोगों का पलायन होता है । इस कारण शहरों पर दबाव बढ़ जाता है और जल प्रदूषण की समस्या हो जाती है । जल प्रदूषित होने से लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, ये तो सामाजिक प्रभाव हुए, सूखे के आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत अन्न और ऊर्जा की कमी हो जाती है । किसान को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है । उस की उपज कम हो जाती है, वनोपज में कमी हो जाती है और उस को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है । पर्यटन के उद्योग पर भी असर पड़ता है । ये सारी परिस्थितियां हैं जिन के कारण किसान, मजदूर और आम आदमी पर निश्चित रूप से असर पड़ता है । मान्यवर, यह तो मध्य प्रदेश की स्थिति है, लेकिन राजस्थान में भी पिछले 4 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है । इस के अलावा और भी कुछ राज्य हैं जहां कि लगातार सूखा पड़ रहा है । मेरे राजस्थान के साथी बोलेंगे तो वे विस्तार से वहां की स्थिति का जिक्र करेंगे । महोदय, ऐसे कुछ राज्य आइडेंटीफाइ किए जाने चाहिए जहां लगातार सूखा पड़ रहा है और उन के बारे में केन्द्र सरकार की क्या नीति है ? हम कहें कि अमुक राज्य को इतना पैसा दे दिया, लेकिन वे राज्य जहां लगातार सूखा पड़ रहा है, उन राज्यों के लिए नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है । जहां पीने के पानी की समस्या है तो वहां पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या नीति बनाई गई है, यह देखा जाना चाहिए । महोदय, कर्नाटक में 27 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में सूखे की स्थिति निर्मित हुई है । इस के अलावा पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी सूखे की स्थिति से भी काफी लोग परेशान हैं और स्थिति यह है कि साउथ एशिया में भारत में सब से ज्यादा सूखा पड़ा है । यदि हम बीसवीं और उन्नीसवीं सदी में पड़े सूखे का आंकलन करें तो पाते हैं कि उन्नीसवीं सदी में 25 बार हमारे देश में सूखा पड़ चुका है और अठारहवीं सदी में 20 बार सूखा पड़ चुका है । महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सब के बाद भी हम इस बारे में कोई नीति नहीं बना पाए हैं । हमारे देश में 107 मिलियन हैक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित हो रही है और जब हम इतनी ज्यादा भूमि का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हमारे किसान की हालत बेहतर कैसे होगी ? महोदय, जब किसान की हालत बेहतर नहीं होगी तो देश की हालत बेहतर नहीं हो सकती और जब देश की हालत बेहतर नहीं होगी तो हम गर्व के साथ नहीं कह सकते कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में यह स्थिति निर्मित हो रही है ।

महोदय, यह स्थिति है जिस का मैं जिक्र करना आवश्यक समझता हूं । महोदय, दो-तीन बातों पर गौर करने की जरूरत है । एक बात यह है कि हम जल व्यवस्था का मूल्यांकन बहुत बारीकी से करें, बहुत ईमानदारी से करें और एक समय सीमा के अंदर कोई नीति निर्धारित करें । दूसरी बात, यह कि जहां जल भारी मात्रा में है, उस जल को जहां जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, वहां पहुंचाने की व्यवस्था करें और उपलब्ध प्राकृतिक जल के सही इस्तेमाल के लिए कोई नीति निर्धारित करें । मान्यवर, भाई मिश्र जी ने सही बात कही कि हम एअरकंडीशंड कमरों में बैठे योजनाकारों पर निर्भर होकर ही इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूखे की विभीषिका क्या हुआ करती है, सूखे का दर्द क्या हुआ करता है, इस बारे में, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उन को ज्ञान नहीं होता है, हां अनुभव नहीं होता है । वह उस के दर्द और पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं ।

हमारे यहां अथर्ववेद में कहा गया है कि उपलब्ध जल और संरक्षण के द्वारा सूखा टाला जा सकता है, लेकिन हमारे देश में न तो उपलब्ध जल का सही इस्तेमाल हो पा रहा है और न ही जल संरक्षण ठीक हो पा रहा है । इसलिए अथर्ववेद में कही गई यह बात अपने आप में अक्षरश: सही साबित होती है, जो हमारे यहां सूखा नहीं टल पा रहा है ।

1.00 p.m.

MR. CHAIRMAN: Mr. Pachouri, now, it is one o'clock. You can continue after lunch. The House is adjourned for lunch till two o'clock.

The House then adjourned for lunch at one of the clock

The House reassembled after lunch at two of the clock

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

श्री संघ प्रिय गौतम : नमस्कार मैडम ।

उपसभापति : नमस्कार । हम लोग ड्राउट पर डिस्कशन कर रहे हैं और यहां हाऊस में भी ड्राउट हो रहा है । वैसे तो सब लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करके बोलते हैं कि डिस्कशन करो, डिस्कशन करो और जब डिस्कशन होती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, बारिश शुरू हो गई है ।

उपसभापति : कहां, बाहर हो रही है क्या ?

श्री संघ प्रिय गौतम : नहीं, देश में हो रही है - लखनऊ में हुई, जौनपुर में हुई, कासगंज में हुई ।

उपसभापति : देश तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा, यहां से ही बाहर निकल जाऊं तो बहुत है । सुरेश पचौरी जी, आप कांटीन्यू कीजिए । मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है तो आपको क्या जरूरत है सूखे पर बोलने की ।

श्री सुरेश पचौरी : उपसभापति महोदया, मध्य प्रदेश पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखे की चपेट में है कल कुछ पानी गिरा था, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि लगभग 34 जिले मध्य प्रदेश के सूखे की चपेट में हैं । आपने मध्य प्रदेश की बात छेड़ी है इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ....

उपसभापति : पचौरी जी, एक मिनट । मंत्री जी खाली इतना पूछ रहे थे कि इस चर्चा के लिए चार घंटे का समय है और यह 12:30 बजे शुरू हुई थी, तो जवाब कल कर लेंगे, आज नहीं हो पाएगा । जितना बोलेंगे, उतनी बारिश होगी । तो रिप्लाई कल हो जाएगी ।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मध्य प्रदेश के लगभग 35 जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने की वजह से काफी फसल प्रभावित हुई है, वहां पीने के पानी की भी भयावह स्थिति निर्मित हो गई है और मध्य प्रदेश सरकार ने, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी कृपापूर्वक इसको नोट कर लें कि मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिए 64.23 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की है । पिछले तीन वर्षों से मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने आग्रह किया, लगातार सूखा पड़ रहा है और इसको दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार को जितनी मदद करनी चाहिए थी, उसकी तरफ से उतनी मदद हो नहीं पाई है । कमोवेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ की है । वहां लगभग 30 प्रतिशत फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन सैंट्रल टीम अभी तक छत्तीसगढ विज़िट करने नहीं पहुंच

पाई है । तो यह स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है । आवश्यकता इस बात की है कि जो किसान इस सूखे की वजह से प्रभावित हो रहे हैं उनकी हिम्मत बंधाए रखने के लिए समय पर और समुचित आर्थिक उपाय किए जाने बहुत आवश्यक हैं । इसके साथ ही साथ किसानों की ऋण अदायगी में तथा फसल नुकसान की भरपाई के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, उन्हें उठाए जाने की बहुत जरूरत है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो अभी आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके हिसाब से लगभग 28 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि सूखाग्रस्त है । महोदया, 20वीं सदी में जितनी आपदाएं हुईं, यदि उनका दृष्टावलोकन करें तो हम पाएंगे कि उनमें से 60 आपदाएं सूखे से संबंधित हैं और बाकी दूसरे प्रकार की आपदाएं हैं । तो निश्चित रूप से सूखे की वजह से जो दिक्कत किसानों को उठानी पड़ती है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए एक तो हमें देखना होगा कि उसके मूल में क्या है और दूसरी तरफ हमें यह देखना होगा कि उसके निदान और परमानेंट निदान के लिए क्या कदम उठाए जाने जरूरी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे पूर्वज थे वह बहुत विद्वान, आधुनिक और वैज्ञानिक भले ही न हों लेकिन वह दूरदर्शी थे। दूरदर्शी मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले कोई भी गांव में बसावत होती थी तो कुएं, बावड़ी, तालाब वहां होना आवश्यक था। कुएं, बावड़ी और तालाब का गहरीकरण कैसे हो, कैसे उसका रखरखाव हो इसके लिए लोगों को बताया जाता था लेकिन उस तरफ से हम लोगों का ध्यान किसी न किसी वजह से हट गया। आज जो योजनाकार हैं वह बड़ी-बड़ी योजना तो बना रहे हैं उस चकाचौंध में हम सिमटते ज: रहे हैं लेकिन हमारी जो पहले की व्यवस्था थी, जो पहले के तौर-तरीके थे जल संवर्द्धन के और जल के उपयोग में आने के उनसे हम दूर हटते जा रहे हैं, उन पर बहुत खासा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे बरसात का पानी हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं, उस पानी का हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, केवल हम आधुनिक तरीकों पर ही निर्भर रहेंगे तो निश्चित रूप से यह आधुनिक साधन हमको धोखा देते रहेंगे ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इसलिए जब जल संरक्षण की बात आती है तो जो परम्परागत उपाय थे, जो साधन थे जल संग्रहण करने के लिए उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि आगे सूखा न हो उससे बचने के लिए पक्का इंतजाम करो। पक्का इंतजाम कैसे किया जाए उसके लिए तालाबों के रखरखाव की जरूरत है, उसके लिए कुओं और बावड़ियों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, पेड़ों को बचाने की जरूरत है, जंगल न कट पाएं यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और फिर सूखा न आए इसके लिए कुछ योजना बनाने की जरूरत है। महोदया, प्रश्न यह है कि इसके लिए अभी तक क्या-क्या कार्यक्रम किए गए। हम केवल दोषारोपण इस या उस सरकार को करें इस या उस समय को करें क्योंकि लम्बे समय से सूखा चल रहा है। लेकिन जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उन कदमों में क्या कमी आई है, इस अवसर पर उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक नेशनल लेविल पर वाटर ग्रिड मिशन बनाने का सुझाव आया था। एक डा0 के0एल0 राव की भी एक कमेटी 1972 में बनी थी उसने कुछ सुझाव दिए। उस कमेटी के बाद एक हाशिम कमेटी बनी जिसने 30-9-99 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उन पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। उन पर अमल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन इसके साथ-साथ यह जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील गंभीर मुद्दा है इससे संबंधित जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन पर ज्यादा पैसा आबंटित करने की आवश्यकता है। यद्यपि वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं वरना उनकी उपस्थिति का लाभ लेता लेकिन पूर्व वित्त मंत्री जी हमारे कृषि मंत्री जी के बिल्कुल पड़ोस में बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चल रहे हैं, मरु भूमि विकास कार्यक्रम चल रहे

हैं, समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम चल रहे हैं इसके अलावा पनधाराओं के लिए जो पैसा दिया जाता है, यह पैसा ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो रोजगार आश्वासन योजना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, इन योजनाओं के तहत भी ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आज बहुत आवश्यकता हो गई है। जबकि हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा राज्य सूखे की चपेट में हैं। मैंने कहा कि सूखे का प्रभाव मानव जाति पर ही नहीं पड़ रहा है इसका असर पशु-पक्षियों पर भी पड़ रहा है। पशुओं के लिए जो चारा मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरे प्रदेशों से जो चारा जाए, वह रेलगाड़ियों के जरिए से जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाता है इसमें सरकार की तरफ से जो रियायत मिलनी चाहिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह रेल मंत्री जी से इस बारे में पहल करें कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए जो चारा जाएगा वह बिना शुल्क के जाएगा उसके लिए रेल विभाग कोई पैसा नहीं लेगा। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार का अरेंजमेंट पहले भी किया गया है, पहले भी इस प्रकार की सरकार ने पहल की है। इसके अतिरिक्त महोदया, वाटर ग्रिड जलग्रहण मिशन, मरुस्थल सुधार, परती भूमि सुधार, इन योजनाओं को एक समेकित करके एक दीर्घकालिक योजना बनाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। जैसा मैंने कहा हम इस मानसून सत्र में मानसून न होने की वजह से केवल सूखे से संबंधित चर्चा करके कमियां गिनाएं उससे काम नहीं चलना है। हमें कुछ उपायों के बारे में विचार करना चाहिए। कौन-कौन सी योजनाएं बनाई, कौन-कौन सी सिफारिशें थीं, उन सिफारिशों को मूर्तरूप दें, तभी हम कुछ कर पायेंगे और इसके लिए मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इसके लिए हम जनप्रतिनिधियों को आगे आना होना। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वे राज्य जिन राज्यों में बहुत सूखा पड़ा हुआ है, उन राज्यों से जो जनप्रतिनिधि चुनकर आये हैं, उन्हें एक-एक दिन की तनख्वाह इस सूखा प्रभावित समस्या से निपटने के लिए वालेंटेरिली देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से जो माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, यदि वे भी एक दिन की तनख्वाह दे दें तो मैं सोचता हूं कि यह एक अनुकरणीय पहल होगी। इसका जनमानस में एक प्रभाव जायेगा कि हम लोग संसद में केवल सुझाव ही नहीं देते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं और इस सूखे की समस्या से निपटने के लिए कुछ बोझ को हल्का करने की कोशिश भी करते हैं।

महोदया, मैंने मेट्रोलॉजीकल डिपार्टमेंट के बारे में जिक्र किया था कि हम केवल सूखे की संहिता ही न बनाएं, मौसम संहिता भी बनाएं। मौसम विज्ञान की स्थिति यह है कि 15-20 दिन पहले, यह मेट्रोलॉजीकल डिपार्टमेंट हैं, चूंकि आप स्वयं विज्ञान की एक स्टूडेंट रही हैं, आप इस बात को भली-भांति समझती हैं कि 15-20 दिन पहले ही इस डिपार्टमेंट को बता देना चाहिए कि यहां मानसून आ सकता है और यहां पर नहीं आ सकता है जिससे कि वहां पर पहले से ही प्रिकोशनरी मेजर्स लिए जा सकें। लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। इस दिशा में भी सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : दिल्ली में फेल हो गया। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : क्या फेल हो गया ?

श्री संघ प्रिय गौतम : दिल्ली में मानसून दो दिन में आने वाला था, वह फेल हो गया।

उपसभापति : वेदरमैन हमेशा गलत बोलते हैं।

श्री सुरेश पचौरी: उपसभापति महोदया, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि यदि जल का उचित प्रबधंन हो जाता है तो कृषि का भी अच्छा प्रबंध हो जाता है। जल, समृद्धि और कृषि ये सब एक दूसरे के साथ-साथ चलते हैं। स्थिति यह है कि यदि सूखे की वजह से गांव नष्ट होंगे तो इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा । यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत की संस्कृति, भारत की परम्परा, भारत के संस्कार और भारत की प्राचीनता नष्ट हो जायेगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए। इसलिए देश की दीर्घकालीन और सदैव रहने वाली समस्या के प्रति, खासतौर से सूखे के प्रति हमारा जो रवैया हो, वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हम इसके लिए केवल तात्कालिक उपाय अपनाकर, तात्कालिक भागदौड़ न करें, बल्कि इसका कोई एक परमानेंट साल्युशन निकालें। इसका जो नेशनल वाटर ग्रिड मिशन है और इसके लिए इंटर वाटर बेसिन वाला जो प्रोग्राम है, विभिन्न राज्यों के बीच में जो डिसप्युट्स चल रहे हैं, उन डिसप्युट्स का समय रहते हुए समाधान निकालने की आवश्यकता है। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

महोदया, दो-तीन बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। अभी 2001 तक की जो स्थिति है, उसमें तो केवल 100 मिलियन लोग ही सूखे की वजह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी जो आंकड़े आये हैं, उनके अनुसार 150 मिलियन लोग सूखे की वजह से प्रभावित हुए हैं। लोग तो यह बता रहे हैं कि इसकी वजह से जल संकट भी पैदा हो जायेगा। इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का यह सोचना है कि यदि अगला विश्व युद्ध हुआ तो वह जल पर होगा। इसलिए इस खतरे को भांपते हुए हमें समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। यही मैं आपके जरिए से निवेदन करना चाहता हूं। इस वक्त हम सूखे पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे जो परम्परागत साधन जल संरक्षण के लिए हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। उनके साथ-साथ आधुनिक साधनों का भी हमें उपयोग करना चाहिए ताकि गांव का हर निवासी खुशहाल रह सके, हर किसान खुशहाल रह सके। क्योंकि यदि गांव में रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर शिकन होगी, यदि किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें होंगी तो भारत खुशहाल नहीं बन पायेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सूखे की समस्या से भारत जूझ रहा है, भारत मैं जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि अधिकांश हिस्सा सूखे से जूझ रहा है, इसलिए पूरा भारत जूझ रहा है। इस समस्या को सरकार को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और समय रहते कदम उठाये जाने चाहिए। धन्यवाद।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया, अभी पचौरी जी ने संकेत दिया। यह बात सरकार की ओर से आनी थी, लेकिन मैं एक बहुत छोटी सी सूचना दे रहा हूं, बहुत छोटी बात है हमारे मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। जब मैंने उनसे बात की कि आपकी सारी भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं। देश भटक जाता है, इसका क्या कारण है ? उन्होंने जो कारण बताए, उनमें से एक कारण मैं आपको बताना चाहता हूं ।

उपसभापति : जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा । आप इस तरह से बीच में कैसे बोल रहे हैं?

श्री बालकवि बैरागी : मैडम, केवल दो सैंटेंस कहना चाहता हूं । उन्होंने जो एक बात

कही है, क्योंकि यहां कृषि मंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर उपकरणों के लिए 25 पैसा पर हैड के हिसाब से साल का सरकार की तरफ से मिलता है । कुल मिलाकर 25-30 करोड़ रुपए मिलते हैं, इतने कम पैसे में न हमारे उपकरण आ पाते हैं और न हम काम कर पाते हैं । जो भी बात कहते हैं, वह विश्वास के दायरे से बाहर हो जाती है । यह उनकी वेदना है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पैसे को बढ़ाया जाए । ...**(व्यवधान)**... जी हां, भविष्यवाणी भी बाहर से उधार लेते हैं ।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदया, मुझे सूखे के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस समय पूरे पूर्वोत्तर भारत में सूखे की बड़ी विकराल स्थिति निर्मित हुई है । इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी है कि लोगों ने अनुभव करना शुरू किया है कि अगर त्वरित कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो आने वाले समय में आम जनमानस, विशेष रूप से गांव में रहने वाले लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं । केवल इतना ही नहीं, दुर्दशा तो इस प्रकार की निर्मित होती जा रही है जिसके कारण खरीफ की फसल जो अब इस समय तक काफी तैयार हो जानी चाहिए थी, वह बोयी ही नहीं जा सकी है । स्वयं राष्ट्रीय फसल भविष्यवाणी केन्द्र की तरफ से कहा गया है कि जो 406 लाख हैक्टेयर जमीन पर खरीफ की फसल बोयी जाती थी, इस समय तक उसमें केवल 20 लाख हैक्टेयर तक ही वह फसल बोयी जा सकी है । इतनी अधिक कृषि की जमीन खरीफ की फसल बोये बगैर ही खाली पड़ी है । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में किस प्रकार की स्थिति निर्मित होने वाली है । विशेषकर इस समय मोटे अनाज ही बोए जाते हैं और वह मोटा अनाज सामान्य किसान के लिए, सामान्य मजदूर के लिए, उसका पेट भरने के लिए आवश्यक होता है । लेकिन उसकी यह स्थिति निर्मित हुई है । राष्ट्रीय फसल भविष्यवाणी केन्द्र की तरफ से यह बात भी कही गयी है कि धान की फसल, मोटे अनाज के अंदर बाकी सारी चीजें तो हैं ही, धान की फसल की इस समय तक मात्र 4.18 लाख हैक्टेयर में ही बुवाई हुई है जब कि पिछले साल इस समय तक 10.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में धान बोया जा चुका था । यह इस बात को प्रकट करता है कि पानी न रहने के कारण, वर्षा न होने के कारण कितना जबर्दस्त अंतर आ गया है । यह इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो भविष्य बड़ा भयंकर दिखाई पड़ेगा । इसके बारे में कल्पना करते ही डर लगता है कि क्या होने वाला है । इसी संदर्भ में जब हम मौसम विज्ञान के संबंध में विचार करते हैं और मौसम के बारे में जो सामान्य रूप से जानकारी प्रदान करते रहते हैं, उनकी जानकारी देखकर भी बड़ा आश्चर्य होता है । मैं उसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि आदरणीय श्री जनेश्वर मिश्र जी और पचौरी जी ने उसके संबंध में बताया । हमें तो ध्यान आता है जैसे घाघ का नाम लिया, घाघ कवि कितने बड़े मौसम विज्ञानी थे, आज भी पर्यावरण के संबंध में घाघ की कविताएं बड़ी प्रचलित हैं और मैं समझता हूं कि उसमें से 90 फीसदी से ज्यादा सत्य साबित हुई हैं । अभी भी ऐसा होता है । उनकी एक कहावत है, हमने देखा और आप भी अगर उसका आकलन करें और देखें तो सही सही साबित होता है। उनका कहना है -

"दिन को बदूर, रात भी बिवद्दर, बहे पुरवइया झब्बर झब्बर ।
घाघ कहें हम होव वियोगी, कुआं खोद-खोद कर धोइयँ धोबी।।"

अर्थात् जब दिन में बदली हो और रात में पुरवाई चलती हो तो उस समय सामान्य किसान बड़ा चिंतित हो जाता है कि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है, सूखा होने वाला है । उसके

आधार पर ही किसान अपनी फसल बोता था और अपनी फसल के बारे में सुनिश्चित दिशा निर्धारित करता था । उसी में उन्होंने यह भी कहा है कि बरसात कब होती है । घाघ की सोच पर्यावरण से संबंधित ज्यादा थी, इसलिए इसमें भी उन्होंने यह कहते हुए एक संकेत दिया है -

"ढेले ऊपर चील जो बोले, गली-गली में पानी डोले ।"

चील पक्षी होती है और अगर वह किसी खेत में मिट्टी के धूहे पर बैठकर बोलती है तो समझ लो कि बड़ी जबरदस्त बरसात होने वाली है । इसी तरह वृक्ष पर चलते हुए गिरगिट के बारे में कहा है -

"उलटै गिरगिट ऊंचै चढ़ै, बरसा होइ भूमि जल उड़ै ।"

अगर वृक्ष पर गिरगिट पीछे से ऊपर चढ़ती है तो समझ लो कि बहुत जबरदस्त बरसात होने वाली है और यह होता है । आज भी लोग गांवों में इस बात का आकलन करते हुए कहते हैं कि यह होने वाला है । इतने पर्यावरण विज्ञानी घाघ कवि लोक भाषा में गांववासियों को मौसम के बारे में इतनी योग्य जानकारी देते रहे हैं कि अगर उसका भी समुचित तौर पर सदुपयोग किया गया होता, उसको लेकर देखा जाता तो शायद मौसम विज्ञानियों को लगता कि उसका भी किसी तरीके से समायोजन किया जा सकता था लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मौसम विज्ञानी यह घोषणा तो कर रहे हैं और वे लगातार घोषणा करते जा रहे हैं कि अब मानसून आने वाला है, अब मानसून आने वाला है लेकिन मानसून नहीं आया और पूरा पूर्वोत्तर भारत इसका शिकार हुआ है ।

महोदया, मध्य प्रदेश में भोपाल में एक बड़ी झील है जो अब सूख गई है । पहले वहां मज़ार के पास हम नाव से जाते थे लेकिन अब वह एक प्रकार से पर्यटन स्थल बन गया है और आप वहां अब अपने आप जा सकते हैं । पिछली बार इस समय तक वहां 246 मि.मी. बरसात हुई थी लेकिन इस बार 132 मि.मी. बरसात भी वहां पर नहीं हो पाई है । मैं मध्य प्रदेश के भोपाल के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि वहां के तालाब और कुएं सारे के सारे सूखे पड़े हैं । उनकी हालत बहुत खराब है । उत्तर प्रदेश में तो उससे भी ज्यादा भयंकर दुर्दशा है । केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे प्रदेशों में हालत खराब है और उत्तर प्रदेश में तो पचास से अधिक ज़िले इस समय सूखे से इतने ग्रस्त हैं कि लोगों को लगने लगा है कि अगर यही स्थिति रही तो हम क्या कर पाएंगे? यह ठीक है कि आदरणीय मिश्र जी ने इसके बारे में कई बातें बताईं । प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उसके लिए सरकार क्या करे और बाकी के लोग क्या करें, एक अजीब प्रकार के स्वरूप का निर्माण होता है । यह बात सही है कि शासन के पास साधन होने के कारण उनको सुविधा रहती है कि कुछ अच्छा कर डालें लेकिन इस पर सामूहिकता के साथ विचार करने की आवश्यकता है । इतना ज़बरदस्त अकाल हुआ है, इतनी ज़बरदस्त प्राकृतिक आपदा आई है, इस प्राकृतिक आपदा का सामना हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर करें । यह आरोपित करने का, प्रत्यारोपित करने का अवसर नहीं है । इसलिए एक सामान्य चित्रण और सूखे के कारण वास्तविकता का कैसे निर्माण हुआ है, इसका चित्रण भी करना बहुत ज़रूरी है और चित्रण करने के पश्चात ही सही मायने में उसका समाधान निकाला जा सकता है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है, वह बड़ी विचित्र है । पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के एक सामान्य वातावरण का निर्माण करते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बिहार में जिस तरह से मानसून पहले आ जाता है, उसी प्रकार नेपाल में

अगर बरसात होती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमोत्तर बिहार उसके कारण तबाह हो जाते हैं, भले ही वहां बरसात न होती हो । प्रश्न-काल में इस पर एक चर्चा भी चली थी लेकिन उसका स्वरूप एक भिन्न प्रकार का है, लेकिन वहां भी इस समय भयंकर सूखे की स्थिति का निर्माण हो गया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश भी सूखाग्रस्त हो गया है । उसी तरह से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, ये दोनों मिलकर एक भौगोलिक स्थिति का निर्माण करते हैं । इस समय बुंदेलखंड में इतना भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। जालौन जनपद में सौ फीसदी नुकसान हुआ है। हालत वहां खराब है, कोई फसल इस समय नहीं है। वहां पानी की तबाही मची हुई है। चाहे जालौन हो, चाहे हम्मीरपुर हो, चाहे मोहबा हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे बांदा हो और चाहे चित्रकूट धाम हो, ये सारे बुंदेलखंड के हिस्से हैं। हालांकि कहीं 90 फीसदी का नुकसान, कहीं 100 फीसदी का नुकसान, कहीं 70 फीसदी का नुकसान है। लोग पानी के लिए तरस रहे है। यह बुंदेलखंड की वास्तविक स्थिति का स्वरूप हमारे सामने निर्मित हुआ है और इसी तरीके से मध्य उत्तर प्रदेश को जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ है। चाहे इटावा हो, हमारे रामगोपाल जी वहां के रहने वाले हैं, मैनपुरी हो, ओरैया हो,फर्रूखाबाद हो और कानपुर के आसपास के जिले हैं , वहां भी इसी प्रकार की स्थिति है। 70 फीसदी का नुकसान हुआ है जो आंकलन आया है, जिन्होंने सर्वेक्षण किया है। उस सर्वेक्षण के आधार पर बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मैं तो विशेष रूप से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। वहां की स्थिति तो और खराब हुई है, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि लखनऊ के आठ विकास खंड हैं जिसमें 22655 हैक्टेयर तक खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। किन्तु बरसात न होने के कारण यहां पर लोग तो यह कह रहे हैं कि बोया ही नहीं गया। यहां स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि इस संसदीय क्षेत्र में, विशेष प्राथमिकता के आधार पर काम करने की आवश्यकता है। केवल इतना ही नहीं जहां पर पानी के स्रोत हैं, जहां से हमें लगता है कि हम पानी ले सकते हैं, बांधों के द्वारा जो पानी इकट्ठा किया गया था, वहां से जो जल स्रोत का स्तर है, वहां से भी हम पानी प्राप्त कर सकते थे, वहां भी दुर्दशा निर्मित हुई है और बांधों के जलाशयों का स्तर बड़ी तेजी के साथ गिरा है। इस समय देश के 70 रिजर्वायरों में खतरा है और उसकी क्षमता का केवल 17 फीसदी पानी उपलब्ध हो रहा है। इनमें कुल पानी की उपलब्धता 130.55 अरब घन मीटर थी। पिछले साल की तुलना में यह केवल 66 फीसदी है। 155 लाख हैक्टेयर में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन की स्थिति, इस क्षेत्र में चिंताजनक है। अभी मात्र 44.60 लाख हैक्टेयर में ही यह बुवाई हुई है। पिछले साल इस समय 90 लाख हैक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। सोयाबीन के बारे में हमारे पूर्ववक्ता ने बताया है, मैं बताना चाहूंगा कि 50.09 लाख हैक्टेयर के मुकाबले 17.6 लाख हैक्टेयर की बुवाई हुई है जिससे सोयाबीन का उत्पादन सबसे निम्न स्तर पर पहुंचने की आशंका है। मोटे अनाजों के 232 लाख हैक्टेयर के सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अभी केवल 74 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में ज्वार 6 लाख तथा मक्के की 9 लाख हैक्टेयर में कम बुवाई हुई। खेती की दुर्दशा के कारण सामान्य किसान चाहे खेतिहर किसान हो, चाहे खेतिहर मज़दूर हो। ये इन दोनों के अंदर जो सीमांत कृषक हो ... **(समय की घंटी)**... या खेतिहर मजदूर हो, इन दोनों के अंदर ऐसी स्थिति, ऐसी आशंका पैदा हो गई है कि उनको यह लगने लगा है कि अगर यही अकाल की स्थिति बनी रही, यही सूखे की स्थिति बनी रही तो आगे पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। इस सूखे के कारण, खेती की दुर्दशा हो जाने के कारण, सामान्य आर्थिक विकास दर पर भी इसका जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। पिछली बार कृषि के ऊपर आधारित उद्योग के कारण उद्योग

में, कृषि की उपज के कारण जो विकास दर की बढ़ोत्तरी 5.4 फीसदी थी, इस बार अगर कृषि की यही दुर्दशा रही तो विकास दर की क्या हालत होगी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना सारा होने के बावजूद जो आवश्यकता प्रतीत हो रही है, यह लग रहा है कि पानी मिलना चाहिए और पानी के लिए ट्यूबवैल चाहिए, हैंडपम्प चाहिए। ट्यूबवैल्स की स्थिति यह है कि विद्युत के अभाव के कारण ये चल नहीं रहे हैं। काफी ट्यूबवैल्स खराब हैं। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी खराब स्थिति है। बिजली नहीं मिल रही है । बिजली पर अलग से चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यह भी चर्चा का एक अच्छा विषय है । हम उसमें ये सारे सुझाव दे सकते हैं ।

उपसभापति : दिल्ली में भी नहीं मिल रही है, यह तो कैपिटल है ।

श्री कलराज मिश्र : मैं सामान्य रूप से सभी जगहों के बारे में कहते हुए...**(व्यवधान)**... मीणा जी, मैं सभी के बारे में कहते हुए उत्तर प्रदेश का इसमें जिक्र कर रहा हूं । बाकी जगह भी नहीं मिल रही है और उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है । क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना जरूरी प्रतीत होता है ।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): देहात में तो एक घंटे का भी औसत नहीं है ।

श्री कलराज मिश्र : हालत तो यह है कि जो राजकीय नलकूप हैं वे अधिकांशत: बंद पड़े हैं । वहां लगभग 28,381 राजकीय नलकूप हैं जिनसे 28.3 लाख हैक्टेयर की सिंचाई होती है लेकिन यहां हर दसवें नलकूप पर एक नलकूप खराब है । यहां नलकूप की यह स्थिति निर्मित है । विद्युत के कारण नलकूप नहीं चल रहे हैं । नलकूप खराब भी हैं । हैंडपंप की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वह भी नहीं है । जल शोधन के साधन तालाब आदि भी सूख गए हैं । उसकी त्वरित व्यवस्था करना आवश्यक है । उसकी आकस्मिक व्यवस्था करना आवश्यक है । इसके लिए विशेष प्रकार की योजना बनाना भी जरूरी है ताकि लोगों को पानी प्राप्त हो सके । इतना ही नहीं इस समय जहां से भी राजस्व की वसूली हो रही है, केंद्र सरकार की तरफ से यह निर्देश जाना चाहिए, वैसे मुझे आज ही यह जानकारी मिली है कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से यह फैसला किया है कि वह राजस्व की वसूली बंद कर देगी । वे इस समय कर रहे हैं । बाकी प्रदेशों में जहां बंद नहीं हुई है वहां वसूली स्थगित की जानी चाहिए ताकि किसान कम से कम राहत तो महसूस कर सके । केंद्र की तरफ से जो राष्ट्रीय बीमा योजना थी, फसल बीमा योजना थी, जिन प्रदेशों ने इसे लागू किया है उन प्रदेशों में लागू करने के पश्चात् उन्हें समुचित दाम प्राप्त होने चाहिए । जिन प्रदेशों ने लागू नहीं किया है, पचौरी जी चले गए हैं, मध्य प्रदेश में शायद लागू नहीं किया गया है, जिन प्रदेशों ने इसे लागू नहीं किया है उन प्रदेशों को कड़ाई से निर्देश देना चाहिए कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू करें । बीमा योजना इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को काफी राहत प्रदान करती है । मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने फसल बीमा योजना के बारे में कहा है कि समुचित तौर पर उसका मूल्यांकन करते हुए जहां भी यह लागू हुई है, उसकी व्यवस्था की जाएगी । पानी की भी विशेष रूप से व्यवस्था करने की आवश्यकता है । हमारा पानी का स्तर गिरने के कारण बिजली उत्पादन ठप्प पड़ता चला जा रहा है । मैं विशेष रूप से रिहन्द के बारे में बताना चाहूंगा । रिहन्द से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एन.टी.पी.सी. के कारण भी दिक्कत होगी । वहां का उत्पादन भी घटेगा और उसका परिणाम यह होगा कि हमारे प्रदेश और बाकी जगहों में विद्युत के

अभाव के कारण, विद्युत उत्पादन में कमी के कारण एक जबर्दस्त परेशानी होगी । सूखे के कारण, जल स्तर गिरने के कारण यह हालत होगी । जल स्तर की व्यवस्था कैसे हो, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है । महोदया, इस समय शासन के द्वारा ये प्रयत्न जरूर किए जा रहे हैं । कृषि मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि यह राज्य का विषय है, राज्य का विषय होने के कारण राज्य इसकी व्यवस्था करे लेकिन यह सूखा एक प्राकृतिक आपदा के रूप में आया है । इसलिए इसके प्रति भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है कि वह इसे प्राथमिकता के आधार पर ले । आम आदमी की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए । उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह चाहे जल हो, भोजन हो, काम के बदले अनाज की व्यवस्था हो और चाहे विभिन्न स्कीम्स, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके आधार पर स्किल्ड और अनस्किल्ड श्रमिकों को लगाकर व्यवस्था की जाती है उसे प्रभावी तौर पर चलाया जाए । समेकित योजना हो, जवाहर योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या स्वर्ण जयंती रोजगार योजना हो , इन सारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर इस समय लागू करके लोगों को अधिक से अधिक काम दिलवाने की व्यवस्था की जाए । मैं समझता हूं कि इससे हम इस प्राकृतिक आपदा का काफी हद तक सामना करने में सक्षम हो सकेंगे । महोदया, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री कलराज मिश्र: मैडम, जरा इसमें एक चीज मैं कहना चाहता था। हमारे प्रदेश में जितने भी जिले, लगभग 50 जिले हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको या पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जाए, यह भी हमारी मांग है।

उपसभापति : मतलब वजह बताकर कह रहे हैं कि क्यों घोषित किया जाए। Before Mr. R. Chandra Sekar Reddy speaks, I would like to draw the attention of the House to the fact that four hours have been given for this discussion and we have to finish it today. Now, the problem is, I have to manage the time strictly. So, please try to abide by the time allowed to you. You can't add more 'drought' to what has already been spoken by others. So, the Members may please abide by the time allocated to their party. Twelve minutes have been given to the TDP. Even if you take all the 12 minutes, I have no objection. But if you take 11 minutes, I will be very happy. One minute should be given to the Minister. In fact, the division is not done properly.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on the drought situation in the country. It is ironical that in the Monsoon Session, we are discussing about the drought situation in the country. The entire country is facing a severe drought, and the situation is alarming.

The States like Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Orissa and U.P. are the worst-affected. The rainfall so far has been far below the normal average. The States like Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh

1713 GIPMR/03—16

are also facing this situation. Statistics indicate that more than one million villages are facing a severe drought condition.

As the mercury level has been steadily rising in several States in the last few days, the spectre of a severe drought is hovering over these places. While the drinking water problem is becoming acute in these States, people's misery is compounded by the drying tubewells. These States are reeling under a terrible spell of heat wave. Reports say that even the States like Himachal Pradesh have demanded Rs.20 crores from the Centre to deal with the drought-like situation, as most of the natural water sources in the State have reportedly dried up. The Centre should come forward to help the affected States with liberal financial assistance, and there can be no two opinions about it.

A high powered Committee on Disaster Management Plans was constituted by the Government of India in August, 1999, to review the existing arrangements to mitigate the natural and manmade disasters, to recommend measures for strengthening the organizational structures, and to recommend a comprehensive model plan for the management of these disasters at the national, State and district levels. I am told this committee had submitted its final report in September, 2001. This report should be implemented, in consultation with the State Governments.

The Drought Prone Areas Programme, DPAP, should be implemented more vigorously. Based on the report of the C.H. Hanumantha Rao Committee, the Government has issued revised guidelines for its implementation. I request that more number of watershed programmes should be sanctioned to the States like Andhra Pradesh, Orissa, Rajasthan, Gujarat, etc. Since the basic objective of the programme is to minimize the adverse effects of drought on the production of crops and livestock, maximize the profitability of land, develop the water and human resources, ultimately insulating the areas from the effects of drought. This programme would also create employment opportunities.

Our hon. Agriculture Minister has made a statement, apprehending drought in the North India and Central India. In this regard, I would like to draw his attention to the severe drought situation in Andhra Pradesh and Orissa also.

In Andhra Pradesh, during the first week of June, there were some rains, but thereafter, the State is experiencing a dry spell. The actual rainfall during this monsoon is less than 100 mm, the deficiency being more than

60%. The State is in the throes of a severe drought, and about 900 *mandals* are badly affected.

As against a total cultivated area of 82 lakh hectares, so far, sowing has taken place in less than 20% of the area. The major cause of concern is with regard to dry crops like pulses, groundnut, maize, and bajra. Due to continued dry spell the crops have withered away. Paddy nurseries are withering away.

Due to failure of monsoon, the ponds and reservoirs have run dry. The ground water table has fallen to a new low due to poor recharge in the absence of rain.

Madam, our hon. Chief Minister, Shri N. Chandra Babu Naidu, is taking every step to alleviate the alarming drought situation by ordering the necessary measures. But the situation is so grave that the State Government alone cannot face it. Hence, I request the Government of India to extend financial assistance for the on-going irrigation projects in the State and to support the programme called ***Neeru-Meeru*** -- Water and You. This is a very unique programme started in the State of Andhra Pradesh. Under this Programme, the Government is undertaking measures to de-silt the irrigation tanks. It is a unique programme. It should be implemented throughout the country. Under this programme all the tanks, which were constructed prior to our Independence, are de-silted. Under this Programme -- ***Neeru-Meeru*** -- we are giving employment to labour, we are also increasing the storage capacity in all the tanks and we are able to give water to the tail-end areas of the irrigated land which fall under these tanks. The Government of India, under the Food-for-Work Programme, had sent some foodgrains to the State. I request that this Programme should be continued with an increased allocation. The State Government is ably handling the Food-for-Work Programme. Employment problem, to some extent, is solved through this Programme and we could fill the belly of the hungry people, apart from creating permanent assets in the rural areas. We are thankful to the Government of India for allocating foodgrains to us under this Programme.

The State is also facing power problem. All the hydel stations that are generating power stopped generating power since the reservoirs have become empty. I request the Government of India to help the State in meeting the power demand also.

I request the Government to allot more number of houses under the VAMBAY and IAY. These two Programmes will create employment

opportunities and a permanent asset to the poor people who are homeless. Madam, adequate funds may be allocated to the State for providing drinking water as the sources are drying up and water table is going down due to severe drought. I request the Government of India to come to the rescue of the States like Andhra Pradesh. As we all know Andhra Pradesh is a performing State. Any amount of money given to the State is perfectly spent in the concerned area and all the targeted programmes reach the needy people. Hence, I request the Government of India to give a special concession to the State by providing more money for providing drinking water to all the people.

Madam, increase in allocation to all the rural development *programmes will help the people in this hour of crisis. The crop insurance* scheme should be extended to all the farmers and the rules which are detrimental to the interests of farmers relaxed. The crop insurance scheme is a very good scheme. But there are some problems. When farmers approach the lower-level officers, they put so many conditions. As a result, the genuine farmer, who has lost his crop, is facing a lot of hardship in getting his money reimbursed. Hence, I request the Government to not only extend this programme to all the farmers but also to relax the rules which are causing a lot of trouble to the small and marginal farmers in the rural areas.

Finally, I request the Government of India to help the State, on a permanent basis, as the State is experiencing drought for many consecutive years. I come from the most backward area. We have regularly been experiencing the drought conditions. Since the State of Andhra Pradesh is facing a severe drought for the past several years, I request the Government of India to give assistance on a permanent basis as per the rules, which are guiding the States and the Central Government. I am also requesting the Government of India to enhance the National Calamity Relief Fund. On the one hand, the grant is very meagre. It is not helping the State. On the other hand, when the States are facing such a problem, the Government of India is advising them to go ahead with the programme and saying that they can claim their reimbursement afterwards. But, as a matter of fact, the amount kept in the National Calamity Relief Fund is not sufficient and so, is not serving its purpose. Since the entire country is facing a drought situation, the amount in the Fund should be enhanced.

The States should be given a free hand in spending the money from the National Calamity Fund, depending upon the situation, depending

upon the severity of the drought. I, once again, request the hon. Minister to come over to Andhra Pradesh and visit the drought-affected areas and help the State Government, which is right now involved in helping the poor farmers and poor labourers. As we started debating in this House, Madam, I was told that there is slight drizzling in Andhra Pradesh. The hon. Minister may say that rains have started in Andhra Pradesh, in Orissa and in other parts of the country. But these 'rains' will not at all help the farmers. It would not be useful for farming community. It would also not be of help to anybody, except cooling the atmosphere. Hence, I request the Government of India to go all out and help the State Government in helping the poor and downtrodden people in the rural areas.

डा0 अलादी पी0 राजकुमार : मैडम, मुझे एक बात एड करनी है । मैं सुबह कृषि मंत्री जी से बात कर रहा था । हमारे यहां कल से बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश से फार्मर्स को बेनेफिट नहीं होगा क्योंकि हमारे यहां मानसून तो जून के फर्स्ट वीक से आने वाला था, वह नहीं आया । Fifty days have passed, and the total crop has been destroyed. Therefore, my humble request is that the hon. Agriculture Minister should take up this matter with the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister, and should provide, at least, Rs. 1000 crores for the National Calamity Relief Fund. This is not for Andhra Pradesh only. I am talking about the entire country which is facing a severe drought in some areas. Rs. 150 crores that had been given by the then hon. Finance was not sufficient at all. That amount could last only for three months. That money has been exhausted in dealing with the cyclone and drought situations. Therefore, I sincerely appeal to the hon. Agriculture Minister to sit with the Prime Minister and demand, at least, Rs. 1000 crores for the National Calamity Relief Fund. Kindly come to Hyderabad and visit drought-affected areas. The Minister said that we were getting water. There may be some improvement in the availability of drinking water. But the farmers are not going to be benefited from that. This is my humble request, through you, to the hon. Agriculture Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There was a suggestion by Mr. Pachouri that we may give one month's salary for the drought-affected areas. Now, I have also one suggestion. Each Member of this House and the other House gets Rs. 2 crores as MPLADS fund. Why can't we invest a part of that money for digging the catchment areas so that whatever rain comes could be collected? This is an asset-building activity that we have stopped. Even if its rains, it goes down the drain. You had contributed a lot for Orissa cyclone, you had contributed much more for Gujarat

earthquake. This is also a national calamity. Your own States are facing it. So, as the Chairman of the Committee on MPLADS, I would suggest that we can spend that money for this purpose also, instead of just spending it on making roads or laying pavements, etc. This work will give jobs also to the people. You will also be able to collect the water and use it.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Desitling of medium and major tanks have been done in Andhra Pradesh. The MPLADS funds have been used for this purpose only. We welcome your suggestion. But Andhra Pradesh is already doing this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When I am having a meeting, I will examine how many Members of Parliament have contributed money for this purpose. You know, even water harvesting can be done. That we are going to do in Gujarat...or, you know, even water harvesting can be done as we are doing in Gujarat. Now I will call Mr. Matilal Sarkar of CPI (M). You have 12 minutes, Mr. Sarkar. You can take all the time.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): At the outset, I offer my sincere regards to you and to my senior colleagues here on the occasion of my maiden speech in this House. While speaking on drought during this Monsoon Session, we observe that though this is a Monsoon Session, Monsoon has bid a goodbye to a large part of our country. It is not something unusual. Whenever there is heavy rainfall, there is a genuine reason behind it. Similarly, whenever there is a deficiency in rainfall, there is a reason behind it. And, whenever there are floods or droughts, there is a reason behind it. We are passing through a revolutionary age of technology. We can convert hotness into coldness and coldness into hotness. Science has developed so much! Now, the only thing required is good planning. We should not start thinking about checking or arresting drought after it occurs. But, we should make a comprehensive plan beforehand because our Government knows which part of the country has heavy rainfall and which part has less rainfall. There is nothing unusual in the fact that drought comes every year. The map is before us, and we are aware of the geography of our country; the only thing is, planning should be made on the basis of what is going on. At present, about 320 districts of the country are seriously affected by drought.

So far as rainfall is concerned, it is below the normal figure by about 15 per cent. If we see the figures of the past years, the area covered by rainfall seems to be like this. In the year 2000, 9.3 per cent of the area

covered had excess rainfall. In 2001, it covered 5.2 per cent area. In 2000, 61.2 per cent of the area had normal rainfall. In 2001, it was 84.4 per cent. In 2000, 29.5 per cent area had deficient rainfall. In 2001, it was 10.4 per cent. This year the rainfall is less than the normal figure and the figure has not yet come out. At least, I don't have the figures. It is a fact that Monsoon started a bit earlier in the South East and in the North East also.

At least, I do not know this. But it is a fact that monsoon reached a little earlier in the South-East and the North-East, while in the rest of the country, the rainfall is negligible. By giving all this information, I want to draw the attention of the Government to the totality of the situation as far as rainfall in various States is concerned. The situation is almost the same. We have to see how we can overcome this situation. Drought has affected -- I do not want to remention all the States -- Rajasthan, Madhya Pradesh, Chattisgarh, Karnataka and even irrigated areas of Haryana and Punjab. Crops have been affected. There is a heavy loss of production in Bajara, Soyabean, groundnuts, pulses, cotton, and kharif crops in various States. More important point is, drought and floods never come alone. Many things like rural unemployment, poverty, etc. accompany them. The agricultural labour becomes jobless. As a result, poverty increases. During drought, ponds dry up. As a result, people also face drinking water problems. Besides, drought brings various diseases with it. Every year, in our country, in Kalahandi area of Orissa, a large number of people die of starvation. Is it not known to the Government? I want to know why it happens like this every year. If the Government seriously thinks over this matter, I think, we can overcome the situation. Besides human beings, animals also die of starvation. I have some reports with me but I will not quote them because it is a lengthy information and I do not want to take much time of the House. On the one hand, we are facing drought-like situation in many parts of the country; on the other hand, there are heavy floods in some other parts. So, there is a need to discuss droughts and floods simultaneously. Presently, the North-Eastern region of Assam and, partially, Bengal also, are facing flood like situations. On the one hand, drought brings with it sufferings; on the other hand, floods take away property and life.

One thing is, how can these onslaughts caused by floods and drought be arrested? Of course, the Government comes up with relief programmes. Madam, we have seen how the State Government of Tripura tackled the whole situation with boldness the year before last year. The

3.00 p.m.

relief went there, but it was not adequate. It went there after quite some time. Perhaps, in the year 1999, -- if I am not wrong -- the State of West Bengal had also experienced the same thing. The havoc caused by floods had damaged thousands of acres of land in West Bengal. The relief did not go there. Perhaps, it reached after a long time. *...(Time-bell)...* Madam, I will take only two more minutes. It is my maiden speech.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Maiden speech does mean that we start getting floods.

SHRI MATILAL SARKAR: Madam, I have not taken even ten minutes. Now, what has been the experience there, in West Bengal? They have the same experience. It has happened in West Bengal and Tripura. The other States did not have such an experience. So there is discrimination. There is a lot of discrimination in giving relief, in distributing money from the National Calamity Relief Fund. This type of discrimination is causing a lot of problems to these States. In the matter of tackling drought and floods, there should not be any politics. We cannot politicise such things. I would urge upon the Government to refrain from such an attitude. What should be done when we are faced with a drought? Have the Government thought about alternative crops, short duration crops? Have the Government thought about giving direct compensation to the victims, to the cultivators, to the agricultural labourers? Have the Government thought of helping those who are affected by drought, by giving them alternative means of livelihood? There is the 'Food for Work' Programme. But how much money has been given under the 'Food for Work' Programme? Is it of the order that all the affected people could be accommodated? Sir, I would suggest that there should be three types of remedial works. One is that, there should be direct help to the victims and, further, it should come promptly. It should not be like a fire brigade coming after the house is burnt. That type of help is meaningless. So, there should be immediate relief to those who are affected. And, as a short-term relief, alternative crops could be thought of. But in order to tackle such calamities, like drought, floods, etc., there should be a comprehensive plan on the part of the Government so that we could identify the causes and precautionary measures could be taken at an appropriate time. If the Government is sincere enough to take up such schemes, it will not be very difficult for them to handle the situation. Only the intention is required.

While concluding, I will just give one example. In China, the river Wanghou was once called the River of Curse. But, now, it has been converted into a River of Blessings. So, the manpower, accompanied by science, can bring about such revolutionary changes in the field of agriculture and social life. In the end, I would say that there is rainfall in our country, but, water drains out through the rivers into the seas. But let not the relief works drain out in this manner. With these few words, I conclude my speech.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ramachandra Khuntia. Mr. Khuntia, I have to tell you one thing. There are three speakers from your party. Mr. Pachouri has already taken half-an-hour. Now, the remaining time has to be divided between you and Mr. Ahmed. Okay.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Madam Deputy Chairperson, I stand here to participate in the discussion on the drought situation prevailing in Andhra Pradesh, West Bengal, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and my State, Orissa. The situation is very serious and alarming, and it is a matter of great concern for all of us. I would like to say something, particularly about Orissa. In Orissa, in 1998, there was a drought; in 1999,. there was a super-cyclone; in 2000, again, there was a drought; in 2001, there were floods, and in 2002, again, there is a drought. So, the situation is very serious and alarming in the State of Orissa. I would like to draw the attention of the House to two things. I would like to quote a newsitem which has appeared in the Economic Times of 16th July, 2002:

> "The meteorological department's forecast of a fifteenth successive 'normal' monsoon seems to have gone awfully wrong. As on 12th July, 20 out of 36 meteorological sub-divisions were deficient in rainfall."

Madam, my point is, the Meteorological Department is there to predict about the weather. What went wrong? Why has the prediction gone wrong? I think, this thing must be inquired into. It is a matter of great concern for the whole country. How has the prediction gone wrong? Why have the people who are engaged in this field not given a correct prediction? Is it a mechanical failure or is it due to some human error?

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is an El Nino effect over the monsoon. It changes all over the world.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Maybe. But, in this modern era, to say that everything is natural calamity, whether it is drought or whether it is flood, and the human beings have nothing to do, is not a correct thing. I think, the human beings have a role to play, and in the modern era, the Government can also do something to find out where the mistake has taken place. There was a scheme, called the Drought-Prone Area Programme. I want to know specifically about the total money spent by the Government on this scheme, and the amount of money received by each State. I would also like to know whether the Government of India is aware of the fact that many of the State Governments have not utilised this money at all. Therefore, from 1973, till today, we are not getting the expected results from this programme. Somebody said that there was some rain in Orissa, Andhra Pradesh and some other areas. I want to put it on record that rain at this time is not useful when the farming system is completely damaged. I also come from a farmers family. I know about it. It may be useful in bringing down the temperature; it may be useful for providing drinking water. But it is not useful for farming purposes. In the western parts of Orissa, there is no rain, and there is not a drop of water. I want to give some suggestions. If you go into the details, you will find that, sometimes, the State Governments and the Central Government, instead of giving help and assistance, are creating problems for the farmers. Take the case of crop insurance. In some areas, it is said, as far as relief is concerned, that if the damage is less than 50 per cent, the farmers are not eligible to get any sort of benefit, including crop insurance. That is wrong. If a person loses 40 per cent of the crop, he should get 40 per cent compensation. Why should he not get anything? In the old Relief Code, it is mentioned that if the crop loss is less than 50 per cent, it should not be declared as a drought-affected area. This is wrong. I think this norm should be changed. As regards crop insurance in my State, it is said that only those who are taking loans through the societies are eligible to get compensation under the crop insurance scheme, and persons who are not taking loans and investing their own money are not eligible to get any compensation under the crop insurance scheme. This is also wrong. There is another point which I had brought to the notice of the Finance Minister, and which could not be resolved till date. There is a scheme with respect to fertilizer retail shops. In a general situation, in case there is a burglary, the agents will get the claim. But in the case of a super cyclone, if there is some loss, the agents will not get the claim. Of course, the agents in Gujarat get the claim. This is gross injustice. There cannot be a discrimination between one State

and another under an insurance scheme. If anybody is getting the benefit, all the people should get the benefit. Why should there be a discrimination between Gujarat and Orissa? This insurance scheme should also facilitate the farmers to get the claim. The farmers should not be deprived of their legitimate claim under this scheme.

Madam, I would also like to mention about lift irrigation in Orissa. I am sorry to say. There are 15,200 lift irrigation points in Orissa which can provide water to 3 lakh hectares of land. At least, these 3 lakh hectares of land could have been saved, if they had been properly utilised. But, now, the World Bank, the IMF and the DFID are there in the State. What the Orissa Government wants to do is to hold discussions with the DFID; and it wants to revive the Lift Irrigation Corporation and give the lift irrigation points to the farmers in the name of *pani* panchayat. But it is not working, and the farmers are not getting the benefit. Out of the 15,200 lift irrigation points, only 500 lift irrigation points have been handed over to the farmers in the last two years. The State Government says that unless the farmers take over the lift irrigation points, it will not give water, even if there is famine or drought. The Government of Orissa is not allowing the farmers to take water from these 15,200 lift irrigation points. If they had been allowed to take water, 3 lakh hectares of agricultural land in Orissa could have been saved. So, I urge upon the Government of India to give necessary instructions to the State Government to give water to the farmers. The Government of India should give adequate assistance for the repair and maintenance of the existing lift irrigation points and also for providing more lift irrigation points. In the north and other parts of India, sufficient groundwater is not available. But in the case of eastern parts of the country, only 16-18% of the groundwater is utilised. There is adequate groundwater in the eastern parts of the country. The Central Government should give adequate funds for providing and maintaining these lift irrigation points. Some Members have mentioned about the KBK districts. We all know about the KBK districts where starvation deaths are still going on. There is one programme for the KBK districts, which is also being implemented. I am sorry to inform the House that the long-term action plan in regard to the KBK districts, which was given to the Government of India by the State Government, has not been approved so far by the Planning Commission.

I would like to make one more point. The State Government has no money to spend on any developmental work or any other programme.

The State Government has taken a loan of Rs. 23,000 crores and they are paying an interest of Rs. 3,000 crores every year. They do not have money to spend. Whatever money is given to the Orissa Government that money does not reach the people. There is a demand from the State Government of Orissa and from all parts of the State to declare Orissa as a special-category State and give more assistance to the State so that it can come out of the grave situation. When the Prime Minister came to Orissa, he assured that the demand of declaring Orissa as a special-category State would be considered. But nothing has been done so far.

Madam, so far as coal royalty is concerned, the coal royalty has not been revised since 1996. Orissa is the worst affected State. Even the Finance Commission had recommended that those coal producing States should be compensated adequately where coal royalty has not been increased. If coal royalty is increased, Orissa would be able to get more than Rs. 1,000 crores and would become stable financially. Until and unless the State Government has financial stability and utilises the money which is given by the Central Government, the State cannot deliver goods.

I would like to make one more point. The Agriculture Minister who is sitting here is very much interested in the cause of farmers. As I mentioned earlier, the farmers of Orissa are committing suicide because they have not been able to sell their paddy. The Government price of paddy is Rs. 520/- to Rs. 580/- per quintal. But they are bound to sell it at Rs. 250/- to Rs. 400/- per quintal; whereas the price of paddy is Rs. 2.50/- to Rs. 4/- per kg. The farmers are purchasing seeds at a rate of Rs. 10/- per kg. Now the fertilizer subsidy has also been reduced. So the farmers are not able to sell the paddy. It is a related issue. If the farmer is not able to sell the produce, he would not be interested in cultivation. Unless and until the farmers are interested in cultivation, the farming community, the agriculture workers which constitute 80 per cent of our population, will be out of job.

I urge upon the Agriculture Minister to look into this matter and give necessary instructions to the FCI to procure paddy at an appropriate price.

I join my other colleagues who have spoken on this subject. The Government must have a contingency plan. We all know which are the areas affected by floods every year. So we must have a contingency plan. The plan which was made in 1973, has proved to be a failure. It has not

served the purpose. The Government must think about it seriously and prepare an action plan to meet the grave situation in the country. As I mentioned earlier, the situation in many parts of the country especially in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa is very alarming. It may become a famine like situation and hundreds of people might die due to starvation if the situation is not controlled. Therefore, the Government of India must think about it seriously and take appropriate action before anything happens.

INFORMATION TO THE HOUSE RE. RESULT OF PRESIDENTIAL ELECTION - 2002

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to make an announcement in the House. The Returning Officer, Shri R.C. Tripathi, who is the Secretary-General of Rajya Sabha, after the counting of the votes for the Presidential election, under the Presidential and the Vice-Presidential Elections Act 1952, has declared Shri A.P.J. Abul Kalam as the President of India.

He has got 89.58 per cent votes. This House sends its congratulations to the newly elected President. Parliament means the President and both the Houses of Parliament. So, he is a part of us.

AN HON. MEMBER: Madam, can you tell us how many votes were polled in his favour?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He got 9,22,884 votes and the second candidate got 1,07,366 votes.

I have another announcement to make. Shri P. Prabhakar Reddy has been appointed as the new Vice-Chairperson on the Panel and I would like to give him a chance to preside the House. I hope you will all co-operate with him. Shri Reddy, I suppose, you are a lawyer. Don't use too much of law. I am not a lawyer. I am, basically, a scientist. But the main thing is running the House, which is, mainly, with the co-operation of the Members and not really the Rules book nor the knowledge of law. But, I am quite sure, you will be a good Vice-Chairperson on the Panel. And I request the entire House to be co-operative with him. When he rings the bell, please sit down.

[उपसभाध्यक्ष (श्री पी.प्रभाकर रेड्डी) पीठासीन हुए]